गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 034
दि. 03.06.2026, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

10 जून को पीएम मोदी रचेंगे इतिहास, कांग्रेस को लगेगा झटका, तोड़ देंगे नेहरू का रिकॉर्ड

(जीएनएस)।

इस 10 जून को पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं. वे नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. और इसी के साथ पीएम मोदी लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे लंबे समय तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं. इस दिन मोदी स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता बन जाएंगे. इस मामले में वह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे.

नेहरू 13 मई 1952 को पहले आम चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे. इसके बाद 27 मई 1964 को अपने निधन तक वह लगातार प्रधानमंत्री रहे. इस अवधि में उनका कार्यकाल 4,397 दिनों का रहा.

वहीं नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. 9 जून 2026 को उनका कार्यकाल 4,397 दिनों का हो जाएगा, जो नेहरू के बराबर होगा. 10 जून 2026 को मोदी का कार्यकाल 4,398 दिनों का हो जाएगा और इसी के साथ वह निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर बने रहने वाले नेता बन जाएंगे.

एक के बाद एक टूट रहे हैं कांग्रेस युग के रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस काल के कई बड़े राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. जुलाई 2025 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार 4,077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था. इसके बाद मोदी लगातार कार्यकाल के मामले में नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे.

अब 10 जून को वह नेहरू का भी रिकॉर्ड पार कर लेंगे और निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले नेता बन जाएंगे.

फिर भी कायम रहेगा नेहरू का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

हालांकि कुल प्रधानमंत्री कार्यकाल के मामले में जवाहरलाल नेहरू अभी भी पहले स्थान पर बने हुए हैं. नेहरू 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 तक पद पर रहे. इस तरह उनका कुल कार्यकाल लगभग 6,131 दिनों का रहा, जो आज भी भारत में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है.

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय देश में अभी संविधान लागू नहीं हुआ था और न ही स्वतंत्र भारत के लिए कोई आम चुनाव हुआ था.

1947 मे पंडित नेहरू कैसे बने देश के प्रधानमंत्री?

1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया शुरू की. संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था, प्रत्यक्ष जनता के वोट से नहीं. उस समय इण्डियन नेशनल कान्फ्रेंश संविधान सभा में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी.

कांग्रेस ने जवाहर लाल नेहरू को अपना नेता चुना. 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार (I»»fterim Gover»»fme»»ft) बनी, जिसमें वे वाइस प्रेसीडेंट आफ एक्जिक्यूटिव कौंसिल थे. व्यवहारिक रूप से यही पद प्रधानमंत्री के समान था.

जब 15 अगस्त 1947 को भारत

स्वतंत्र हुआ, तो तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड माउंट बेटन ने नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई.

क्या नेहरू 1947 मे चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे? जवाब है नहीं. 1947 में नेहरू किसी लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नहीं बने थे, क्योंकि उस समयः लोकसभा अस्तित्व में नहीं थी.

भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था. देश में पहला आम चुनाव नहीं हुआ था.

पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कब बने?

भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ. इसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और 13 मई 1952 को नेहरू ने फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. इस प्रकार वे भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने.

एक और कीर्तिमान पीएम मोदी के नाम- तीसरी बार लगातार बहुमत से सत्ता में लौटने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी.

नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले गैर-कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बनाई है.

पीएम मोदी के ओडिशा दौरे की तैयारियां तेज, गतिशक्ति पोर्टल से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार

(जीएनएस)।

भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित ओडिशा दौरे से पहले राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में लोक सेवा भवन में लोक निर्माण, कानून एवं आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री गतिशक्ति (पीएम गतिशक्ति) पोर्टल के प्रभावी उपयोग, विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति तथा प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान होने वाले शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन प्रक्रिया को तेज किया जाए।

बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल भविष्य में ओडिशा के आधारभूत ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पोर्टल विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ परियोजनाओं की बेहतर योजना बनाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करेगा।

समीक्षा बैठक में राज्य में प्रस्तावित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सड़क संरेखण (रोड एलाइनमेंट), मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और विकास कार्यों की प्रगति का भी आकलन किया गया। अधिकारियों ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर भी विचार-विमर्श किया।

बैठक का एक अहम एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित ओडिशा दौरे की तैयारियां भी रहीं। इस दौरान राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। सरकार इन परियोजनाओं को राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर मान रही है।

'मच्छर और माफिया दोनों खत्म किए', कुशीनगर में बोले सीएम योगी- 'फाजिलनगर' का नाम अब 'पावागढ़' होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक जनसभा के दौरान 424 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला. इसके साथ ही उन्होंने भगवान महावीर से जुड़े ऐतिहासिक फाजिलनगर का नाम बदलकर 'पावागढ़' करने का एक बड़ा प्रशासनिक ऐलान भी किया.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके जिले को प्रगति की नई राह दिखाई. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद तमकुही राज और पावा नगर की पवित्र भूमि पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनसभा को

संबोधित किया. उन्होंने विपक्ष की सरकारों में रहे पहचान के संकट, जंगल पार्टी के आतंक और विभिन्न माफियाओं के राज को खत्म करने के उद्देश्य से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों की मांग को स्वीकार करते हुए फाजिलनगर का नाम बदलकर 'पावागढ़' करने का आधिकारिक प्रस्ताव रखने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मच्छर और माफिया दोनों का इलाज कर उन्हें जड़ से खत्म किया गया. बीमारी भी दूर और क्राइम भी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरानी स्थिति की याद दिलाते हुए कहा कि करीब नौ-दस साल पहले कुशीनगर पहचान और बीमारी के संकट से जूझ रहा था. उस दौर में यहां खनन माफिया, बालू माफिया और 'जंगल पार्टी' का भारी आतंक था. आज की 25 वर्ष से कम उम्र की युवा पीढ़ी उस खौफ और अराजकता को शायद जानती भी नहीं होगी. इसके अलावा, इंसेफ्लाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी यहां के मासूम बच्चों की जान ले रही थी और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में थी.

प्रधानमंत्री ने सूरत दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत जिले में हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी दुर्घटनास्थल पर हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि इस घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया: गुजरात के सूरत जिले में हुई दुर्घटना के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ।

असम के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी, केंद्र का रहेगा पूरा सहयोग: श्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में राज्य से संबंधित विषयों पर बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में असम में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में असम के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फंड और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने राज्य को कृषि अवसंरचना कोष (AIF), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), मनरेगा तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एजेंडे पर सचिव श्री रोहित कंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और मनरेगा प्रणाली की तकनीकी बाधाओं को पूरी तरह दूर कर दिया गया है। मनरेगा के तहत असम सरकार की मांग के अनुरूप राशि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 1 जुलाई से देशभर में मनरेगा की जगह विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) लागू किया जाएगा।

बैठक में असम सरकार द्वारा चाय बागान (टी-गार्डन) श्रमिकों को भूमि का मालिकाना हक (पट्टा) प्रदान किए जाने के ऐतिहासिक कदम की सराहना की गई। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि इन श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार एक विशेष सर्वे विंडो खोलेगी, ताकि पात्र लाभार्थियों के नाम डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किए जा सकें।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने असम की विशिष्ट जलवायु और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर तैयार कृषि कार्ययोजना का प्रारूप मुख्यमंत्री श्री सरमा को सौंपा। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में असम ने लक्ष्य से अधिक 9 लाख से ज्यादा 'लखपति दीदी' तैयार कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इन महिलाओं के उद्यमों को और सशक्त बनाने के लिए असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (अअव) के इनक्यूबेटर्स के साथ मिलकर कार्य को गति दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा असम में कृषि यंत्रीकरण तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (फ्ङश) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और निधियों की जानकारी दी गई। कृषि मंत्रालय के सचिव श्री आतिश चंद्र ने मुख्यमंत्री को महिला किसानों को कृषि पावर वीडर उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (टटएड-डढ) के विस्तार पर भी चर्चा हुई।

राज्य में सुरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 1,500 नए बांस पॉलीहाउस स्वीकृत किए गए हैं। कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (फ्ङश) के तहत पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब और खाद्य तेल परीक्षण प्रयोगशाला के भवनों को मंजूरी दी गई है।

'लेबनान पर चुप्पी क्यों?', पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश ने पीएम मोदी से मांगा जवाब

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लेबनान में इजराइली सैन्य कार्रवाई और अमेरिका-ईरान वार्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई और अमेरिका-ईरान के बीच जारी बातचीत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों का सीधा असर भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है।

अमेरिका-ईरान वार्ता का किया जिक्र

जयराम रमेश ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध टालने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। उनके मुताबिक, यदि दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो होर्मुज स्ट्रेट के फिर से सामान्य रूप से खुलने और वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव कम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों का भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से गहरा संबंध है।

इजराइल की कार्रवाई बनी बाधा: कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अब तक बातचीत के अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचने की एक बड़ी वजह लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति नाराजगी जता चुके हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों ने लेबनान में इजराइल के हमलों की आलोचना की है।

प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इजराइल की कार्रवाई और उससे क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ रहे असर को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या तथाकथित 'फादरलैंड' उनके लिए उनकी 'मदरलैंड' से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कांग्रेस के इस बयान के बाद पश्चिम एशिया नीति और भारत के कूटनीतिक रुख को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।

अब घरों में रखें 32000 टन सोने पर सरकार की नजर, पीएम मोदी की अपील से कैसे बचेगा विदेशी मुद्रा भंडार?

(जीएनएस)।

भारत के घर और मंदिरों में पड़ा 32,000 टन सोना देश की बड़ी आर्थिक संपत्ति है. पीएम मोदी का मानना है कि अगर इस सोने को रीसायकल किया जाए, तो आयात बिल कम होगा, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा.

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, भारत में सोना लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. शादी-ब्याह हो या फिर कोई तीज- त्योहार, सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है. लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से नया सोना खरीदने के बजाय घरों में पड़े पुराने सोने को रीसायकल करने की अपील कर रहे हैं. इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते आयात बिल से जुड़ी बड़ी वजहें हैं.

पीएम मोदी ने क्या अपील की है?

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोगों से कहा कि वे नया सोना खरीदने की बजाय घरों और मंदिरों में पड़े सोने को रीसायकल करने पर विचार करें. उनका मानना है कि अगर देश में पहले से मौजूद सोने का सही से उपयोग किया जाए तो विदेशों से सोना मंगाने की जरूरत कम हो जाएगी.

ताइवान के बाद अब साउथ कोरिया ने भारत को पछाड़ा, बना दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार!

भारत में कितना सोना है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय घरों और मंदिरों में करीब 32,000 टन सोना मौजूद है. यह दुनिया के सबसे बड़े निजी गोल्ड स्टॉक में से एक माना जाता है. बड़ी मात्रा में यह सोना लॉकरों और तिजोरियों में पड़ा रहता है और आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाता.

सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है गोल्ड रीसाइक्लिंग?

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है. वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने करीब 72.4 अरब डॉलर का सोना आयात किया. इससे देश पर विदेशी मुद्रा का बड़ा बोझ पड़ता है. हर बार जब भारत सोना आयात करता है, तो भुगतान डॉलर में करना पड़ता है. इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है. सरकार चाहती है कि डॉलर की बचत हो और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना रहे. ज्यादा आयात और कम निर्यात की स्थिति में चालू खाता घाटा बढ़ता है. सोने के आयात में कमी आने से इस घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. एक्सपट्र्स का अनुमान है कि अगर घर और मंदिरों में मौजूद कुल सोने का सिर्फ 1% हिस्सा भी हर साल रीसायकल किया जाए, तो भारत का सोना आयात 25% से 30% तक घट सकता है. इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है.

सम्पादकीय

कमजोर मानसून के चलते लगेगा महंगाई का तड़का, अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित

मौसम विभाग द्वारा 29 मई को जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूर्वानुमान बेहद चिंताजनक का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोर मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चिंतनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना ही रहा है। दूसरी और अब अलनीनों के प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात और भी गंभीर होने की संभावना बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। मजे की बात यह है कि इस साल गमा भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के प्रमुख 166 जलाशयों में बुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। उत्तरी भारत के जलाशयों में 26 तो पश्चिम भारत के जलाशयों में 28 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है। मानसून भी तय समय से बिलंबित हो रहा है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूर्वानुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसापास व इससे अधिक ही रही है।

कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक रहती है तो निति रुप से सिचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो बुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे।

हालांकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्राकृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं।

इबोला से डरे अफ्रीका में हाहाकार के बीच भारत ने बॉक्स में ऐसा क्या भेजा, दुनिया कर रही तारीफ

अमेरिका और ईरान में टकराव थमता नहीं दिख रहा है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया जिसकी तारीफ कई देश कर रहे हैं। दरअसल, इबोला संकट से जूझ रहे अफ्रीका को भारत ने लगातार दूसरी बार मेडिकल सपोर्ट भेजा है। जयशंकर ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

नई दिल्लीः कोरोना महामारी के बाद अब इबोला का कहर कई देशों की टेंशन बढ़ा रहा है। खास तौर से अफ्रीका में इबोला के प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। भारत ने इबोला संकट से जूझ रहे पूरे अफ्रीका में मेडिकल समेत कई जरूरी सपोर्ट भेजा है। ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी सरकार ने ये कदम उठाया हो। भारत ने अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) को 43 टन मेडिकल सहायता की खेप भेजी है। दिल्ली से अफ्रीका में भेजी गई मदद की ये दूसरी किस्त है।

जयशंकर ने शेयर की खास तस्वीरें

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफ्रीका सीडीसी को भेजे गए मेडिकल सपोर्ट जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की है। जयशंकर ने बताया कि इस मेडिकल सहायता में प्रोटेक्टिव गियर, डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग उपकरण, दवाएं और सप्लीमेंट्स शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि यह 43 टन की दूसरी खेप अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को और मजबूत करेगी। इसके साथ ही अफ्रीका यूनियन में इबोला संकट से निपटने में अहम रेस्पॉन्स क्षमताओं को बढ़ाएगी।

भारत की मदद का अफ्रीका ने किया स्वागत

इससे पहले सोमवार को, अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (आ्रू उऊ्र) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (उ्रू) के पूर्वी क्षेत्रों में चल रहे इबोला रेस्पॉन्स प्रयासों में सपोर्ट के लिए भारत की मदद का स्वागत किया था। उन्होंने इबोला की रोकथाम में जरूरी मदद के लिए भारत सरकार की ओर से प्रदान किए गए इमरजेंसी सपोर्ट, इलाज और मेडिकल आपूर्ति की तारीफ की थी। इसने पर एक पोस्ट में कहा कि यह आपूर्ति युगांडा में आ्रू उऊ्र के पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से पहुंचाई गई थी और पूर्वी अ्र्र में प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए भेजी गई थी।

इबोला से जूझ रहे कई अफ्रीकी देश

इस महाद्वीपीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि यह सहायता इबोला प्रकोप को नियंत्रित करने और प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के चल रहे प्रयासों को मजबूत करेगी। इसने भारत की ओर से लगातार जारी समर्थन के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार और भारत की जनता को धन्यवाद देते हैं।

अफ्रीका सीडीसी ने भारत के मदद पर दिया ये रिएक्शन

अफ्रीका सीडीसी, जो अफ्रीकी संघ की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी है।

ये पूरे महाद्वीप में बीमारी की रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इससे पहले 29 मई को, भारत ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीका को आपातकालीन मेडिकल आपूर्ति की अपनी पहली खेप भेजने की पुष्टि की थी।

इससे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में बिगड़ते बुंडिबुग्यो इबोला प्रकोप से निपटने में सहायता मिल सके।

नई दिल्ली ने दोहराया है कि वह अफ्रीकी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और जैसे-जैसे स्थिति बदलेगी, वह मेडिकल और रसद सहायता की अगली किस्त भी भेजने के लिए तैयार है।

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की ढाई घंटे की बैठक के क्या हैं मायने? कैबिनेट में जल्द हो सकता है फेरबदल!

(जीएनएस)।

जयपुर , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लंबी बैठक के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले भाजपा सरकार और संगठन स्तर पर कुछ बड़े फैसले ले सकती है।

नियुक्तियों की चचार्एं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि निकाय और पंचायत चुनावों से पहले भाजपा संगठन और सरकार स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच हुई करीब ढाई घंटे की महत्वपूर्ण बैठक के बाद राजस्थान की राजनीति में नई चचाओं ने जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और लंबित राजनीतिक

20 जून से पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार संभवः 10 जून को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक; ये दो मंत्री देंगे इस्तीफा

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के कामकाज, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न बोर्ड, निगम, आयोग तथा सरकारी संस्थानों में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मंथन किए जाने की चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए भाजपा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की दिशा में कदम उठा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा सकता है। वहीं, राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

संगठन को मजबूती मिलेगी

प्रदेश भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार इन नियुक्तियों पर फैसला करती है तो इससे संगठन को मजबूती मिलने के साथ-साथ कार्यकताओं में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।हालांकि, मुख्यमंत्री के नेतृत्व को लेकर किसी प्रकार के बदलाव की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा नेतृत्व पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि राजस्थान में सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही कार्य करती रहेगी। पार्टी का फोकस विकास कार्यों, सुशासन और आगामी चुनावी तैयारियों पर बना हुआ है।

अब राजनीतिक हलकों की नजर भाजपा नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई घोषणा होती है, तो इसे आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जाएगा।

डोंबिवली के पिंपलेश्वर महादेव मंदिर की क्या है खासियत? 20 साल की लड़ाई के बाद मिली जीत, होगा भव्य शिवोत्सव

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र के डोंबिवली के प्रसिद्ध पिंपलेश्वर महादेव मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। क्‍योंकि इस मंदिर से जुड़ा करीब दो दशक पुराना भूमि विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। महाराष्‍ट्र की महायुति सरकार की ओर से मंदिर को 4 एकड़ 25 गुंठा जमीन देवस्थान के अधिकार में देने के फैसले के बाद पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल है। श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक इस निर्णय को आस्था और संघर्ष की जीत मान रहे हैं।

डोंबिवली स्थित पिंपलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा प्रकरण सिर्फ एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और सामूहिक शक्ति का सशक्त उदाहरण है। हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने लगभग दो दशकों तक संघर्ष किया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मंदिर के लिए 4 एकड़ 25 गुंठा भूमि अंततः मंजूर कर दी।

संकल्प पूर्ति पूजन के साथ हुआ आभार व्यक्त

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रविंद्र चव्हाण ने सोमवार तड़के अपनी पत्नी के साथ मंदिर में संकल्प पूर्ति पूजन किया। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह कदम हजारों शिवभक्तों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है।

दो दशक का संघर्ष, आखिरकार मिली जीत

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंदिर की 4 एकड़ से अधिक भूमि को आधिकारिक रूप से मंदिर ट्रस्ट के नाम करने का निर्णय लिया गया, जिससे भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला है। रविंद्र चव्हाण ने बताया कि यह मुद्दा करीब 20 साल से लंबित था। ग्राम सभाओं, प्रशासनिक बैठकों और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए लगातार प्रयास किए जाते रहे। 2012 में डोंबिवली बंद जैसे आंदोलन भी हुए, जिसके बाद अब जाकर यह मामला सुलझ पाया है।

8 जून को होगा भव्य शिवोत्सव

इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में 8 जून 2026 को मंदिर परिसर में भव्य शिवोत्सव और कृतज्ञता समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें भजन-कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक प्रार्थना जैसे कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे और उद्योग मंत्री उदय सामंत सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

श्री पिंपलेश्वर महादेव मंदिर की क्या है खासियत?

डोंबिवली (पूर्व) के नांदिवली-सागाव क्षेत्र में स्थित श्री पिंपलेश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और गहरी धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है। लगभग 125 वर्ष पुराने इस जागृत देवस्थान की स्थापना स्वामी शिवानंद नामक एक तपस्वी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे की थी, जिससे इसकी आध्यात्मिक परंपरा और भी विशेष मानी जाती है।

यह मंदिर कल्याण-शिळ रोड के पास लगभग सात एकड़ के शांत और हरियाली से भरे परिसर में स्थित है, जो इसे एक प्राकृतिक तीर्थ स्थल का स्वरूप देता है। इसकी महिमा को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसे 'क' दर्जा तीर्थक्षेत्र का स्थान भी प्रदान किया है।

यहां हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और पूरा परिसर भक्ति और उत्सव के माहौल से भर जाता है।

शिवभक्तों की आस्था की जीत

चव्हाण ने कहा कि पिंपलेश्वर महादेव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भूमि विवाद खत्म होने से अब मंदिर में सुविधाओं के विकास का रास्ता भी साफ हो गया है। उन्होंने सभी शिवभक्तों और नागरिकों से 8 जून के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।

आरसीबी का अनमोल हीरा, ट्रायल्स में हुआ रिजेक्ट, फिर फाइनल में मैच पलटकर कोहली की टीम को बनाया चैंपियन

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस (GT) को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जब चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की। इस जीत के बाद आरसीबी के अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के साथ एक और नाम पूरी दुनिया की जुबान पर है। यहां हम बात कर रहे हैं युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार की। मेगा ऑक्शन में आरसीबी द्वारा 6 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदे गए रसिक ने इस सीजन में टीम के मुख्य ट्रम्प कार्ड की भूमिका निभाई।

रसिक सलाम डार के लिए शानदार रहा आईपीएल 2026

रसिक सलाम डार ने इस सीजन में 21.30 की शानदार औसत से कुल 19 विकेट चटकाए। इसके साथ ही वह टूनार्मेंट के आठवें सबसे सफल गेंदबाज भी रहे। इतना ही नहीं खिताबी यानी फाइनल मुकाबले में 3 अहम विकेट लेकर आरसीबी की जीत सुनिश्चित की। रसिक सलाम डार ने इस सीजन कई बार आरसीबी को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने का काम कर चुके हैं।

इरफान ने पहचाना था रसिक का टैलेंट

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले रसिक सलाम हर साल श्रीनगर में होने वाले क्रिकेट ट्रायल्स में हिस्सा लेते थे। लेकिन हर बार उन्हें शॉर्टलिस्ट न होने के कारण निराशा हाथ लगती थी। साल 2018 में भी जब वे ट्रायल देकर बिना किसी उम्मीद के अपना किटबैग उठाकर चचेरे भाई नदीम डार के साथ वापस लौट रहे थे, तब पूर्व भारतीय दिग्गज इरफान पठान की नजर उन पर पड़ी। इरफान ने रसिक के कलाई के अनूठे एक्शन और रफ्तार को तुरंत पहचान लिया। इरफान के विशेष प्रयासों के बाद रसिक को सीनियर अभ्यास मैचों में शामिल किया गया, जहां उन्होंने हैट्रिक लेकर अपनी काबिलियत साबित की।

करियर की शुरूआत में ही लगा था बैन

रसिक की प्रतिभा को देखकर मुंबई इंडियंस (MI) ने उन्हें साल 2019 में अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने डेब्यू भी किया। लेकिन इसके तुरंत बाद जन्म प्रमाण पत्र में विसंगति के कारण बीसीसीआई ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। जब वे इस मानसिक आघात से उबरकर वापसी की तैयारी कर रहे थे, तब वे गंभीर रूप से चोटिल हो गए। रसिक को बेंगलुरु में करीब 6 महीने अकेले रहकर कड़े पुनर्वास से गुजरना पड़ा। इस कड़े दौर में उन्होंने अपनी गेंदबाजी तकनीक और एक्शन पर काम किया। बाद में घरेलू क्रिकेट में वे जम्मू-कश्मीर छोड़कर बड़ौदा की तरफ से खेलने लगे।

आरसीबी का दांव और कप्तान पाटीदार का भरोसा

आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक साधारण सीजन के बाद आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में उन पर 6 करोड़ की बड़ी बोली लगाई, जिसे कई विश्लेषकों ने उस समय एक जुआ माना था। लेकिन सीजन में यश दयाल की अनुपस्थिति में कप्तान रजत पाटीदार ने रसिक पर पूरा भरोसा जताया। कप्तान पाटीदार ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि रसिक अपनी स्किल्स, विशेषकर स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी और यॉर्कर को लेकर बेहद स्पष्ट थे। जब भी वे मैदान पर उतरे, उनके पास अपनी भूमिका की पूरी क्लेरिटी थी।

27 छक्के और 400 से ज्यादा रनों से धमाल, आईपीएल के बाद भारत में एक और लीग शुरू, पहले मैच में तहलका

(जीएनएस)।

विदर्भ प्रीमियर लीग 2026 की शुरूआत 1 जून को बेहद रोमांचक अंदाज में हुई। ओपनिंग मुकाबला ठएउड मास्टर ब्लास्टर्स और पगारिया स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया, जिसमें

कुल मिलाकर 442 रन और 27 छक्कों की बरसात देखने को मिली। इस हाई-स्कोरिंग मैच ने लीग के पहले ही दिन फैंस को पूरी तरह एंटरटेन कर दिया। इस मैच की सबसे खास बात रही रविकुमार समर्थ की शानदार शतकीय पारी, जिसने मुकाबले का पूरा रुख ही बदल दिया।

ठएउड मास्टर ब्लास्टर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज तुषार कादू ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 87 रन जड़ दिए। उनकी पारी में 10 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। सबसे खास पल छठे ओवर में आया, जब उन्होंने एक ही ओवर में 33 रन ठोक दिए। यह ओवर पगारिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाज स्वपनिल सिंह ने डाला, जिनके खिलाफ तुषार ने 4 छक्के और 2 चौके जड़कर मैदान में हड़कंप मचा दिया।

इस मैच में गेंदबाज स्वपनिल सिंह भी चर्चा में रहे, जो इससे पहले आईपीएल में फ्ळइ के लिए 7 मैच खेल चुके हैं और 6 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। बल्लेबाजों ने उन्हें जमकर निशाना बनाया और उनकी गेंदबाजी पूरी तरह महंगी साबित हुई। एक ही ओवर में उन्होंने इतने रन लुटा दिए कि वह ओवर लीग के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा ओवर माना जा रहा है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के घर पर चोरी, लाखों के गहने-घड़ियां लेकर फरार हुई थी महिला, पुलिस ने की गिरफ्तारी

(जीएनएस)।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के परिवार से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक्ट्रेस की बुजुर्ग मां के घर से लाखों रुपये के गहने और महंगी घड़ियां गायब होने के बाद पुलिस जांच में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया है। आरोप है कि जिस महिला पर परिवार ने वर्षों तक भरोसा किया, उसी ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

एक्ट्रेस रवीना टंडन के मां के घर पर हुई चोरी

पुलिस जांच के अनुसार गिरफ्तार की गई 47 वर्षीय महिला पिछले कई वर्षों से टंडन परिवार के संपर्क में थी। वह घर के कामकाज में मदद करने के साथ-साथ रवीना टंडन की 86 वर्षीय मां की देखभाल भी करती थी। नियमित रूप से घर आने-जाने के कारण उसने परिवार का विश्वास हासिल कर लिया था और घर के माहौल से पूरी तरह परिचित हो चुकी थी।

भरोसे का फायदा उठाकर महिला ने घर में बनाई जगह

पुलिस के अनुसार इसी भरोसे का फायदा उठाकर उस महिला ने एक्ट्रेस की मां के घर में रखी कीमती संपत्ति पर नजर बनाई और मौका मिलते ही बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया। इस घटना ने एक्ट्रेस के परिवार वालों के साथ साथ उनके करीबियों को भी हैरान कर दिया है।

तिजोरी से गायब हुए लाखों के गहने

-मामला तब सामने आया जब टंडन परिवार ने घर में रखी ज्वैलरी और कुछ महंगी घड़ियों को तलाशना चाहा लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं मिलीं। शुरूआती जांच में पता चला कि कीमती सामान जिस लॉकर में रखा गया था, उससे छेड़छाड़ की गई थी।

-पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला पर आरोप है कि उसने तिजोरी से करीब 25 लाख रुपये के गहने और दो बेशकीमती लग्जरी घड़ियां निकाल ली हैं। परिवार को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत मामले की जांच शुरू की।

पूछताछ में सामने आए कई खुलासे

-शुरूआती पूछताछ के दौरान महिला ने चोरी में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया था। हालांकि बाद में पूछताछ का दायरा बढ़ने पर उसने कथित तौर पर कुछ घड़ियां वापस कर दीं। इसके साथ ही उसने दावा किया कि बाकी गहने किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं और उन्हें जल्द लौटा दिया जाएगा।

-वहीं समय बीतने के बावजूद जब कीमती सामान वापस नहीं मिला, तब परिवार को संदेह और गहरा हो गया। इसके बाद मामले को पुलिस तक पहुंचाया गया।

परिवार को कथित धमकी देने का भी आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी महिला पर परिवार के एक सदस्य को धमकाने का भी आरोप है। कहा जा रहा है कि जब उससे गहनों को लेकर दबाव बनाया गया तो उसने कथित तौर पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। इसी बीच परिवार ने अपने स्तर पर भी सामान की तलाश जारी रखी लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया गया।

शिकायत के बाद तेज हुई पुलिस जांच

-मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद मुंबई के जुहू पुलिस ने जांच शुरू की और उपलब्ध सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और चोरी हुए सामान की बरामदगी के लिए अलग-अलग पहलुओं पर जांच शुरू की।

-फिलहाल पुलिस बाकी ज्वैलरी और अन्य कीमती सामान की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही चोरी की पूरी कड़ी का खुलासा हो सकता है।

रवीना टंडन के परिवार की सुरक्षा पर उठे सवाल

ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि लंबे समय तक बने भरोसे का गलत इस्तेमाल कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रवीना टंडन के परिवार से जुड़ी इस घटना ने न सिर्फ सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं बल्कि ये भी याद दिलाया है कि घर में आने-जाने वाले लोगों पर भरोसा करते समय सतर्कता बरतना कितना जरूरी है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच और चोरी हुए बाकी कीमती सामान की बरामदगी पर टिकी हुई हैं।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

20.39 करोड़ के कार्यों का लोकार्पणः बोले सीएम योगी, ताल-पोखरों को बपौती समझते थे लोग, अब बनता है पर्यटन स्थल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल में 20.39 करोड़ रुपये की पर्यटन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने तालाबों के संरक्षण, इको टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, सोलर प्लांट और स्वच्छता पर जोर देते हुए चिलुआताल को रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की।

(जीएनएस)।

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल में 20.39 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास से संबंधित निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल में प्राकृतिक जल है, लेकिन वहां शहर के पानी को ट्रीट कर छोड़ा जाता है। चिलुआताल में भी प्राकृतिक जल है और इसका शुद्धिकरण किया गया है। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पर अतिक्रमण किया जाता था। उन्हें नष्ट किया जाता था। लोग उन्हें अपनी बपौती समझकर कब्जा कर लेते थे और हवेलियां बना लेते थे। ऐसे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब डबल इंजन वाली सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण कर रही है।

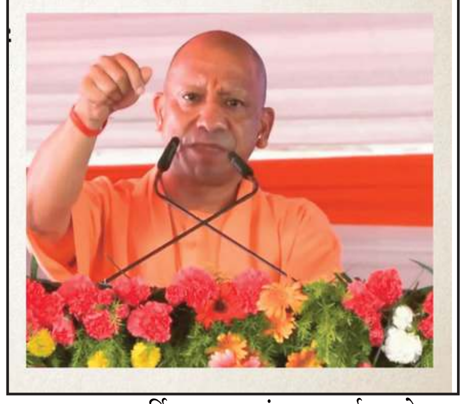

'चिलुआताल में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं'

सीएम योगी ने कहा कि पिछले दिनों रामगढ़ताल में नेशनल रोइंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसमें 22 राज्यों के 243 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सभी प्रतिभागी कहते थे कि इतनी अच्छी झील देखने को कम ही मिलती है। वे लोग यहां आएंगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। रामगढ़ताल के साथ चिलुआताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। यहां दुकानें खुल गई हैं। लोग परिवार के साथ आकर यहां घूम सकते हैं। यहां न प्रदूषण है और न किसी प्रकार की अव्यवस्था। यहां का तापमान भी शहर की तुलना में कम रहता है। पूरी झील से आने वाली ठंडी हवा तापमान को कम बनाए रखती है।

रामगढ़ताल की तर्ज पर किया जाएगा विकसित

यही सिटी डेवलपमेंट प्लान होता है। अब हमारी सिटी केवल स्मार्ट ही नहीं, बल्कि सेफ और सस्टेनेबल सिटी के रूप में भी आगे बढ़ रही है। फर्टिलाइजर प्लांट छह वर्ष पहले तक बंद था। वर्ष 1990 से 2021 तक इसकी गतिविधियां ठप थीं। बीच के समय में यहां एसएसबी आ गई, अन्यथा यहां का स्क्रैप भी गायब हो गया होता। अब यहां एसएसबी, फर्टिलाइजर प्लांट, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय भी हैं। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जब प्रधानमंत्री ने इस फर्टिलाइजर प्लांट का शुभारंभ किया था, तभी इस वाटर बॉडी को विकसित करने का विचार आया था। फर्टिलाइजर प्लांट को जल की आवश्यकता थी। इसे रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित कर इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का हब बनाया जाएगा।

गंदगी न फैलाने की अपील

यहां एक सोलर प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। 20 मेगावाट क्षमता के इस प्लांट से पूरे शहर को बिजली मिलेगी। यह ग्रीन एनर्जी का स्रोत होगा। डबल इंजन की सरकार विकास कार्य कर सकती है। शहरवासियों की भी जिम्मेदारी है कि वे इसे संरक्षित करें। गंदगी न फैलाएं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। यदि कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी शिकायत करें, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। रामगढ़ताल में हाल ही में सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें 56 बोरे कचरा निकला। 5 से 21 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा। चिलुआताल और रामगढ़ताल के आसपास पौधरोपण किया जाए। 4 जून को गंदगी के खिलाफ अभियान चलाकर सफाई की जाए।

मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि रवि किशन उम्र को लेकर मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें बता दें कि उनके सामने हम जेन-जी हैं, नेपाल और बांग्लादेश वाले नहीं।

दोस्ती, छुरेबाजी और नसीहत! सीएम योगी ने खींच दी यूपी चुनाव की लकीर, अपराध पर जीरो टॉलरेंस

गाजियाबाद में बकरीद के मौके पर एक हिंदू युवक सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या और उसके बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई पर विधानसभा चुनाव की बिसात बिछती दिख रही है। योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को यूं ही नहीं धार दे रही है।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरूआत में विधानसभा चुनाव होना है। लखनऊ के सियासी गलियारों और मीडिया बंधुओं के बीच इसे समय से कुछ महीने पहले करवाए जाने की अटकलबाजियां भी चलने लगी हैं। इन सबके बीच गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपियों पर जिस तरह से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है और कर रही है, वह प्रदेश में चुनावी टोन सेट करने का एक बड़ा आधार बनता दिख रहा है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत में अपनी छवि अपराध से मुक्ति दिलाने वाले सीएम के तौर पर बनाई है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, पिछले 9 वर्षों से ज्यादा के उनके शासन काल में जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, वह आम जनता को पसंद आता है, यह कहने में निष्पक्ष से निष्पक्ष व्यक्ति को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।

अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बड़ा एजेंडा

सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया।

इस हत्याकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने की भी तैयारी है।

यूपी में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हाल के वर्षों में नई नहीं है।

लेकिन, सूर्या चौहान का कत्ल और उसके कातिल दोस्त का त्वरित एनकाउंटर कई मायनों में इस संवेदनशील राज्य के लिए अहम है।

असद पर आरोप था कि उसने अपने दोस्त को बकरीद के मौके पर मिलने के लिए बुलाया और उसी की बकरे की तरह कुबार्नी दे दी।

यह घटना सिर्फ हृदयविदारक नहीं है, इंसानियत की दुनिया के लिए बहुत ही असमान्य और रूह कंपा देने वाला हत्याकांड है।

फिर भी समाज का एक वर्ग इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा और इसी के चलते यह मसला बहुत बड़ा चुनावी एजेंडा बनता दिख रहा है।

'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं'

सोमवार (1 जून,2026) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में इस मुद्दे को उठाते हुए एक बार फिर से, लेकिन बहुत ही कड़े अंजाद में चेतावनी दे दी है। मुख्यमंत्री ने ऐसे जघन्य अपराध और उन्हें अंजाम देने वाले अपराधियों से दो टूक कह दिया है- 'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं।...जो अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है, वह गलती कर रहा है।'

एनकाउंटर पर सवाल तो किसे फायदा

सूर्या चौहान एक हिंदू युवक था। आरोप है कि उसके मुस्लिम दोस्त असद ने बकरीद के दिन बेरहमी से तड़पा-तड़पा कर मार डाल और वह भी बकरे की कुबार्नी दिखाने के नाम पर। यह भी आरोप है कि ऐसे हत्यारे के एनकाउंटर पर इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वह मुस्लिम था। ऐसे में यूं कह लें कि बीजेपी को उसी के पिच पर ऐसे बॉल फेंके जा रहे हैं, जिन्हें बाउंडरी के बाहर पहुंचाने में उसे महारत हासिल है।

बंगाल और असम में बीजेपी को मिला लाभ

बीजेपी अभी-अभी असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है। बहुत ही शानदार तरीके से जीती है। वहां भी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जमकर हिंदू-मुस्लिम को मुद्दा बनाया गया। फायदे में बीजेपी रही। फिर भी वहां एक मुस्लिम विधायक ने बकरीद के मौके पर गाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया और उसकी सियासी तपिश यूपी में शुरू हो गई।

'गोमाता राष्ट्रमाता हैं.. आक्रांता हमें न बताए'

बकरीद से पहले यूपी में कुछ मुसलमानों ने यह बयान देना शुरू कर दिया कि अगर गौहत्या हिंदुओं की आस्था पर हमला है तो इसे रोकने के लिए इसे राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसपर भी अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है।

भड़काऊ टिप्पणी करने वालों को चेतावनी

यूपी में कुछ मुस्लिम नेताओं ने बकरीद पर गाय की कुबार्नी का सख्त विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ सोशल मीडिया हैंडलों से माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिशें की गईं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने मौलानाओं से कहा, 'गोमाता के साथ हिमाकत करने वाले चेलों को समझाएं, वरना ऐसी दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी।'

कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरना मुश्किल

सीएम योगी से लाइन मिलते ही डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहकर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह के अपराधियों से पुलिस आगे कैसे निपटने वाली है। अगर इस नीति को 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो-

बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर रत्ती भर समझौता नहीं करने जा रही।

सीएम योगी की सरकार की जो अपराध-विरोधी छवि बनी हुई है, उससे पार्टी टस से मस नहीं होगी।

कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के लिए सरकार को घेरना बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि आम जनता की प्राथमिकताओं में सबसे आगे है।

लखनऊ में सैन्यकर्मी पर महिला को पांच साल बंधक बनाकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन दबाव का आरोप, जांच जारी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने एक सैन्यकर्मी पर पांच वर्षों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

लखनऊ, 2 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने एक सैन्यकर्मी पर पांच वर्षों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, सैरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शिकायत पर 30 मई को सैन्यकर्मी मंजूर अली, उसके भाई कमाल और रिश्तेदार सलमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सोमवार को मुख्य आरोपी मंजूर अली को गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका विवाह सीतापुर जिले में हुआ था। मार्च 2021 में वह अपने मायके सैरपुर स्थित घर आई थी। महिला का आरोप है कि इसी दौरान लखीमपुर खीरी जिले के महंगूखेड़ा निवासी मंजूर अली ने देर रात उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया। शिकायत के अनुसार, इसके बाद आरोपी ने उसे विभिन्न स्थानों पर बंधक बनाकर रखा और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

महिला का आरोप है कि आरोपी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छिपाकर रखता था, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। उसने यह भी आरोप लगाया कि मंजूर अली उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया जाता था।

एफआईआर के अनुसार, जब मंजूर अली ड्यूटी पर जाता था, तब वह महिला को अपने भाई कमाल और रिश्तेदार सलमान के पास छोड़ देता था। पीड़िता का आरोप है कि दोनों उसे जान से मारने की धमकी देकर छिपाकर रखते थे और किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने देते थे।

महिला के अनुसार, कुछ दिन पहले उसे एक पड़ोसी की मदद से अपने पिता से फोन पर संपर्क करने का अवसर मिला। सूचना मिलने पर उसके पिता बताए गए पते पर पहुंचे और उसे वहां से लेकर सैरपुर स्थित अपने घर वापस ले आए। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ में यार्ड ब्लॉक, भोपाल मंडल की 4 ट्रेनें प्रभावित, लखनऊ रूट के यात्रियों को होगी परेशानी

(जीएनएस)।

भोपाल , लखनऊ मंडल में यार्ड ब्लॉक के कारण भोपाल मंडल से गुजरने वाली चार प्रमुख ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दो ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण किया गया है, जबकि दो ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है।

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में चल रहे यार्ड ब्लॉक का असर अब भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी दिखाई देने लगा है। रेलवे ने चार महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इनमें कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है तो कुछ को गंतव्य स्टेशन से पहले ही समाप्त किया जाएगा। इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

लखनऊ तक नहीं पहुंचेगी यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 22683 यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस 1 जून को अपने निर्धारित गंतव्य लखनऊ तक नहीं जाएगी। यह ट्रेन उतरेटिया स्टेशन पर ही समाप्त कर दी जाएगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 22684 लखनऊ-यशवंतपुर एक्सप्रेस 4 जून को लखनऊ के बजाय उतरेटिया स्टेशन से ही रवाना होगी।

दो ट्रेनों का बदला मार्ग

यार्ड ब्लॉक के कारण गाड़ी संख्या 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है। यह ट्रेन 1 से 3 जून तक अपने नियमित मार्ग मानक नगर-लखनऊ-मल्हौर के बजाय मानक नगर-ऐशबाग-मल्हौर होकर संचालित होगी। इस दौरान ट्रेन लखनऊ स्टेशन नहीं जाएगी और उसकी जगह ऐशबाग तथा बादशाह नगर स्टेशन पर ठहराव रहेगा। वहीं गाड़ी संख्या 12173 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस 2 जून को कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-रायबरेली-प्रतापगढ़ मार्ग के बजाय कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-फाफामऊ-प्रतापगढ़ होकर चलेगी। इसके चलते ट्रेन लखनऊ, रायबरेली और अमेठी स्टेशन नहीं पहुंचेगी। यात्रियों को प्रयागराज स्टेशन से वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

यात्रा से पहले जांच लें ट्रेन की स्थिति

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति अवश्य जांच लें। यार्ड ब्लॉक के चलते अंतिम समय में भी परिचालन संबंधी बदलाव संभव हैं। यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 या एनटीईएस के माध्यम से अपनी ट्रेन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या है अमेरिका की धारा 301 ? जिस पर भारत मांग रहा गारंटी, दिल्ली ने खेला मास्टरस्ट्रोक!

(जीएनएस)।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित Trade Deal को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिसमें भारत की शर्त ने डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों देशों के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझौते के मसौदे पर काम जारी है। हालांकि, नई दिल्ली चाहती है कि भविष्य में अमेरिका ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे इस समझौते के तहत मिलने वाले फायदे कमजोर पड़ जाएं। खासतौर पर भारत की चिंता अमेरिकी ट्रेड कानून की धारा 301 (Section 301) को लेकर है। जानेंगे क्या है धारा 301 और क्या है शर्त।

टैरिफ रद्द होने के बाद बदली अमेरिका की नीति

इस साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कुछ जवाबी टैरिफ को रद्द कर दिया था। ये टैरिफ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत लगाए गए थे। अदालती फैसले के बाद अमेरिका ने व्यापारिक कार्रवाई के लिए दूसरे कानूनी विकल्पों पर ध्यान देना शुरू किया। इनमें सबसे अहम है TrÔde Act 1974 की Section 301, जो अमेरिका को विदेशी व्यापारिक नीतियों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर सीधे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देती है।

भारत समेत कई देशों पर चल रही है जांच

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने इस समय कई देशों के खिलाफ Section 301 के तहत जांच शुरू कर रखी है। इस सूची में भारत, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, सिंगापुर समेत कई देश शामिल हैं। इन जांचों का असर भारत के कुछ सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इंडियन इंडस्ट्री और सरकार दोनों इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं।

नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी ट्रेड सेक्रेटरी

सोमवार को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच के अगुवाई में एक अमेरिकी डेलिगेशन नई दिल्ली पहुंचा। उनका यह दौरा भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत के नए दौर की शुरूआत माना जा रहा है। दोनों पक्ष व्यापारिक मतभेदों को कम करने की कोशिश में जुटे हैं।

भारत को Section 301 से क्यों है चिंता?

भारत और अमेरिका फरवरी 2026 से व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के अधिकारी टैरिफ, बाजार तक पहुंच और रेगुलेटर बाधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

लेकिन ट्रंप प्रशासन के पुराने टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद अमेरिका का ध्यान Section 301 की तरफ चला गया। भारत को डर है कि अगर व्यापार समझौते के तहत वह अमेरिकी वस्तुओं को छूट देता है और बाद में अमेरिका Section 301 के जरिए भारतीय उत्पादों पर नए टैरिफ लगा देता है, तो भारत को दोहरा नुकसान हो सकता है।

भारत की क्या है मांग?

भारतीय रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं कि एग्रीमेंट को फाइन करने से पहले अमेरिका टैरिफ को लेकर स्पष्ट आश्वासन दे। बातचीत से जुड़े एक भारतीय सूत्र ने रॉयटर्स से कहा, "भारत को टैरिफ दर, Section 301 जांच के प्रभाव और कॉम्प्टीटिव टैरिफ अरेंजमेंट्स पर चर्चा करनी होगी।" सूत्र ने यह भी कहा कि यदि शर्तें ट्रांसपेरेंट, बैलेंस और जस्टिफाइड होती हैं तो समझौता जल्द पूरा हो सकता है।

आखिर क्या है Section 301?

Trade Act 1974 की Section 301 अमेरिकन ट्रेड सेक्रेटरी ऑफिस को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी विदेशी देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जांच करे यदि उसे लगता है कि वे अमेरिकी व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि जांच में अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि कोई देश अनुचित व्यापारिक रवैया अपना रहा है, तो अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है, इम्पोर्ट में कमी ला सकता है या पहले दी गई व्यापारिक रियायतें वापस ले सकता है।

किन कारणों से शुरू होती है Section 301 जांच?

Section 301 जांच कई कारणों से शुरू हो सकती है। इनमें इंटेलेक्चुअल कॉपी राइट, जबरन टेक्नोलॉडी ट्रांसफर, लेबल लॉ का उल्लंघन, विदेशी बाजारों में पहुंच की बाधाएं, भेदभावपूर्ण नियम और सरकारी सब्सिडी जैसे मुद्दे शामिल हैं। यही वजह है कि इसे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक हथियारों में से एक माना जाता है।

WTO से अलग क्यों है Section 301?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में किसी विवाद को सुलझाने के लिए लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। लेकिन Section 301 के तहत अमेरिका खुद जांच करता है, खुद फैसला लेता है और जरूरत पड़ने पर खुद ही कार्रवाई भी कर सकता है। यही कारण है कि कई देश इसे एकतरफा व्यापारिक दबाव का टूल मानते हैं।

ट्रंप के दौर में फिर चर्चा में आया कानून

1980 के दशक में यह कानून काफी इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि WTO बनने के बाद इसका उपयोग कम हो गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन पर लगाए गए भारी टैरिफ का कानूनी आधार भी यही Section 301 था। अब IEEPA टैरिफ को कानूनी झटका मिलने के बाद यह कानून फिर से अमेरिकी व्यापार नीति का अहम हिस्सा बन गया है।

अमेरिका में 320,000,000 मच्छर क्यों छोड़ रहा गूगल? डेंगू रोकने का प्लान या फैलाने का?

(जीएनएस)।

मच्छर आमतौर पर लोगों के लिए परेशानी की वजह बनते हैं, लेकिन अब Google एक ऐसा प्लान लेकर आया है जिसमें वह खुद करोड़ों मच्छरों को खुले में छोड़ना चाहता है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इससे डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और वेस्ट नाइल वायरस जैसी खतरनाक बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

इसी वजह से Google ने अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा राज्यों में कुल 3.2 करोड़ खास नस्ल के मच्छर छोड़ने की परमीशन मांगी है। यह पहल दुनिया भर में बढ़ रही मच्छर जनित बीमारियों से निपटने की कोशिशों का हिस्सा मानी जा रही है।

एढअ कर रही है प्रस्ताव की जांच

इस समय अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) Google की मच्छर नियंत्रण प्रोजेक्ट "Debug" से जुड़े प्रस्ताव की जांच कर रही है। फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित नोटिस के मुताबिक, इस योजना के तहत दो साल तक हर साल 1.6 करोड़ मच्छर छोड़े जाएंगे। यानी दो साल में कुल 3.2 करोड़ मच्छरों को खुले वातावरण में छोड़ा जा सकता है। इस प्रस्ताव पर 5 जून तक सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद एढअ अंतिम फैसला लेगी कि इस

योजना को मंजूरी दी जाए या नहीं।

आखिर कौन से मच्छर छोड़े जाएंगे?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि Google आखिर किस तरह के मच्छर छोड़ना चाहता है? यह प्रोजेक्ट "Wolbachia" नामक एक प्राकृतिक बैक्टीरिया पर आधारित है। वैज्ञानिक इस बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को तैयार करते हैं और फिर उन्हें खुले वातावरण में छोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर मच्छर इंसानों को काटते नहीं हैं और न ही किसी तरह की बीमारी फैलाते हैं। इसलिए इनसे सीधे तौर पर लोगों को कोई खतरा नहीं होता।

जब ये Wolbachia-संक्रमित नर मच्छर सामान्य मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं, तो उनसे पैदा होने वाले अंडों से ऐसा मच्छर या यूं कहें की मच्छरों की अगली जनरेशन पैदा होती है जो किसी काम की नहीं होती। न ये आगे प्रजनन कर पाते हैं और न ही किसी को काट सकते हैं।। इसका असर यह होता है कि समय के साथ मच्छरों की नई पीढ़ियां कम होती जाती हैं। लगातार कई पीढ़ियों तक यह प्रक्रिया चलने पर मच्छरों की कुल आबादी तेजी से घटने लगती है। यानी यह तकनीक मच्छरों को मारने की बजाय उनकी संख्या को प्राकृतिक तरीके से कम करने पर काम करती है।

यह पूरा कार्यक्रम Google की मूल कंपनी Alphabet के लाइफ साइंस और टेक्नोलॉजी डिवीजन द्वारा डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट का फोकस खास तौर पर Aedes aegypt प्रजाति के मच्छरों पर है। यही वह मच्छर है जो डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया और Yellow Fever जैसी गंभीर बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दुनिया के कई देशों में डेंगू और जीका के बढ़ते मामलों के पीछे इसी मच्छर की बड़ी भूमिका रही है।

Debug Program सिर्फ मच्छर छोड़ने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा टेक्नोलॉजी नेटवर्क काम करता है। Google की टीम बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लाखों नर मच्छरों का उत्पादन, उनकी छंटाई और वितरण करती है। कंपनी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मच्छरों को तैयार करना और सही जगहों तक पहुंचाना बिना आधुनिक तकनीक के संभव नहीं है।

रायरंगपुर में जुटेगी देश की टॉप लीडरशिप, राष्ट्रपति मुर्मु और पीएम मोदी देंगे ओडिशा को बड़ी सौगातें

भुवनेश्वर। ओडिशा में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 20 जून को मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की स्वीकृति मिल चुकी है। दोनों शीर्ष नेताओं की मौजूदगी को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

कार्यक्रम की रूपरेखा और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और आम लोगों की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उपस्थिति वाला यह कार्यक्रम राज्य के लिए गौरव का विषय है। ऐसे में आयोजन की प्रत्येक व्यवस्था उच्च स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने को कहा।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे राज्य के बुनियादी ढांचे, उद्योग, संपर्क व्यवस्था और जनकल्याण योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।

रायरंगपुर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का गृह क्षेत्र होने के कारण इस कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस समारोह को राज्य के राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव अनु गर्ग, विकास आयुक्त डी.के. सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शाश्वत मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

लखनऊ की आलिया रिजवी ने कतरन से बनाई कठपुतलियां, पर्यावरण संदेश से जीता अंतरराष्ट्रीय मंच

(जीएनएस)।

लखनऊ। शहर की गलियों में बिखरे कपड़ों के छोटे-छोटे टुकड़े शायद ही किसी का ध्यान खींचते हों। दर्जियों की दुकानों के बाहर पड़े कतरन के ढेर अधिकांश लोगों के लिए बेकार होते हैं, लेकिन 14 वर्षीय आलिया फातिमा रिजवी ने इन्हीं टुकड़ों में एक नया सपना देखा। ऐसा सपना, जिसने न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत कर दिया।

लॉ मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज की कक्षा नौ की छात्रा आलिया का चयन प्रतिष्ठित स्लिंगशाट चैलेंज में हुआ है, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक और डिज्नी आयोजित करते हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्हें एक हजार डालर की पुरस्कार राशि भी मिलेगी, जो वर्तमान विनिमय दर के अनुसार लगभग 95 से 96 हजार रुपये के बराबर है।

आलिया बताती हैं कि इस विचार की शुरूआत किसी प्रयोगशाला या बड़े शोध केंद्र में नहीं, बल्कि लखनऊ की सड़कों पर हुई। जब वह अपने माता-पिता के साथ पुराने बाजारों में जाती थीं, तब अक्सर दर्जियों की दुकानों और सिलाई केंद्रों के बाहर कपड़ों की कतरनें बिखरी दिखाई देती थीं।

उनके मन में सवाल उठता था कि आखिर इन कपड़ों का क्या होता होगा। अधिकांश कतरन कचरे में चली जाती थी। यहीं से उनके मन में विचार आया कि क्यों न लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए और बेकार समझी जाने वाली सामग्री को उपयोगी बनाया जाए।

इसी दौरान उन्हें लखनऊ की प्रसिद्ध गुलाबो-सिताबो परंपरा याद आई। कठपुतलियों के माध्यम से कहानी कहने की यह कला शहर की पहचान रही है। आलिया ने सोचा कि यदि कपड़ों की कतरन से कठपुतलियां बनाई जाएं और उनके जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाए, तो एक साथ दो काम हो सकते हैं कचरा कम होगा और लखनऊ की विरासत भी नई पीढ़ी तक पहुंचेगी।

इसके बाद उन्होंने स्क्रैप फैब्रिक और अन्य बेकार सामग्री से कठपुतलियां बनाने की अवधारणा पर काम शुरू किया। उनका माडल केवल वस्तुएं बनाने तक सीमित नहीं है।

इसमें बच्चों को शामिल करना, कार्यशालाएं आयोजित करना और कहानियों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना भी शामिल है। उनका मानना है कि बच्चे किताबों की तुलना में कहानियों और गतिविधियों से अधिक सीखते हैं।

आलिया के प्रयासों का असर स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। वे लगातार अपने आसपास के बच्चों और साथियों को समझाती हैं कि किसी भी वस्तु को तुरंत कचरा मानकर फेंकना जरूरी नहीं है।

उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। कई बच्चे और युवा उनके विचारों से प्रेरित होकर बेकार सामग्री से उपयोगी वस्तुएं बनाने और पर्यावरण से जुड़े छोटे-छोटे प्रयास करने लगे हैं।

यह वैश्विक प्रतियोगिता दुनिया भर के युवाओं को पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के व्यावहारिक और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। इस वर्ष इसमें 100 से अधिक देशों के हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आलिया के अनूठे विचार ने शीर्ष में अपनी जगह बनाई।

साथ ही आगामी अक्टूबर में उन्हें वाशिंगटन डीसी (अमेरिका) आमंत्रित किया गया है, जहां दुनिया भर के युवा चेंजमेकर्स के साथ उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

आलिया कहती हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या बड़े संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर बदलाव ला सकता है। उनका संदेश है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, जबकि प्रयास और सीख हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए कभी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा कुछ नया तथा सकारात्मक करने की कोशिश करनी चाहिए।

सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में आलिया ने यह साबित कर दिया है कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी उम्र की नहीं, बड़ी सोच की जरूरत होती है। लखनऊ की गलियों में बिखरी कपड़ों की कतरन से शुरू हुई यह कहानी आज अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी है। यह केवल एक छात्रा की सफलता नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजने वाली सोच दुनिया भर में पहचान बना सकती है।

उत्तर भारत में वर्कशाप की योजना

आलिया ने अपने प्रोजेक्ट में प्रस्ताव रखा है कि उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कठपुतली निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। इन वर्कशाप में बच्चे खुद कतरन से कठपुतलियां बनाना सीखेंगे। इसके बाद, इन्हीं कठपुतलियों के जरिये नाटक और कहानियों के माध्यम से बच्चों को कचरा प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

सीएम योगी जनता दर्शनः सीएम योगी बोले- हर पात्र तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, पुलिस करे दबंगों पर कठोर कार्रवाई

(जीएनएस)।

गोरखपुर, सोमवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। आवास से लेकर इलाज तक, बिटिया की पढ़ाई व विवाह से लेकर निराश्रितों व बुजुर्गों की पेंशन तक, समाज के हर जरूरतमंद के लिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं।

सभी पात्र लोगों से आवेदन कराकर इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। सीएम योगी मंगलवार को जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। सोमवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।

इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास सहित अन्य योजनाओं का

लाभ दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है।

उन्होंने लोगों से कहा कि वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन जरूर करें। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति का संबंधित योजना में आवेदन कराकर लाभ दिलाया जाए। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों के प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए।

अधिकारी जन समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। जनता दर्शन में इस बार भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी।

जनता दर्शन में जौनपुर जिले से आई एक महिला ने एक एनजीओ पर फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ जांच की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामले में जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाए।

जमीन कब्जा किए जाने से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें खूब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए चॉकलेट दीं।

मंदिर की गोशाला में सीएम योगी ने की गोसेवा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा भी की। उन्होंने स्नेहिल थपकी देकर गायों-गोवंश को दुलारा और अपने हाथों से गुड़-रोटी खिलाई। उन्होंने गोशाला के कार्यकताओं को गोवंश की समुचित देखभाल के निर्देश दिए।

लखनऊ की तर्ज पर प्रयागराज में होंगे भव्य स्वागत द्वार, पर्यटकों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन करेंगे

प्रयागराज। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तर्ज पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने शहर के प्रमुख मार्गों और फ्लाईओवर व आरओबी पर स्वागत द्वार लगाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही अलोपीबाग फ्लाईओवर पर सबसे पहले आकर्षक स्वागत द्वार लगवाया जाएगा, जो संगम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अभिनंदन करेगा।

एक सप्ताह में अलोपीबाग फ्लाईओवर पर स्वागत द्वार

अलोपीबाग फ्लाईओवर पर एक सप्ताह के भीतर इसे लगा दिया जाएगा। रात में आकर्षक लाइट से यह द्वार प्रकाशवान रहेगा। स्वागत द्वार में अंग्रेजी में वेलकम प्रयागराज और हिंदी में तीर्थराज प्रयाग या फिर संगम नगरी लिखा रहेगा।

झूंसी, फाफामऊ, चौफटका और नैनी आदि क्षेत्रों में स्वागत द्वार लगाया जाएगा। शहर के सभी इंट्री प्वाइंट को आकर्षक बनाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। पीडीए की ओर से इलेक्ट्रिक स्वागत द्वार का मॉडल तैयार कराया जा चुका है। शहर के प्रमुख स्थानों पर इसे लगाने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दो माह में सभी स्वागत द्वार लग जाएगा।

दिव्य व भव्य स्वागत द्वार लगेगा : पीडीए उपाध्यक्ष

पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज ने बताया कि अलोपीबाग फ्लाईओवर के दोनों छोर पर दिव्य और भव्य स्वागत द्वार लगेगा। स्वागत द्वार बनाने के लिए 16 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। बताया कि आने वाले दिनों में सिक्स लेन पुल, फाफामऊ पुल, गंगा और यमुना पुल सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रवेश द्वार लगाया जाएगा।

हज-2026; लखनऊ एयरपोर्ट पर हाजियों की वापसी शुरू, 430 यात्रियों का हुआ स्वागत

हाजियों ने सकुशल हज यात्रा सम्पन्न कराने और वापसी पर की गई व्यवस्थाओं के लिए हज कमेटी के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया.

(जीएनएस)।

लखनऊः हज-2026 के लिए लखनऊ उड़ान स्थल से वापसी उड़ानों का सिलसिला 1 जून 2026 की रात 10:15 बजे से शुरू हो गया है, जो कि 17 जून 2026 तक जारी रहेगा. पहली वापसी उड़ान से आए 430 हज यात्रियों का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश हज कमेटी की ओर से स्वागत किया गया.

उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारिक ने उन्हें गुलाब का फूल देकर स्वागत किया. इसके साथ ही यात्रियों को जमजम का पानी उपलब्ध कराया गया. उनके सामान की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सहयोग भी सुनिश्चित किया गया. हाजियों ने सकुशल हज यात्रा सम्पन्न कराने और वापसी पर की गई व्यवस्थाओं के लिए हज कमेटी के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया.

हालांकि इस बार हाजियों के

स्वागत समारोह में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला. हर साल हज यात्रियों की वापसी पर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष दानिश आजाद अंसारी स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर हाजियों का स्वागत करते रहे थे, लेकिन इस बार वह एयरपोर्ट नहीं पहुंचे. इतना ही नहीं, हज कमेटी अध्यक्ष के सहयोगी और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी स्वागत कार्यक्रम में नजर नहीं आए. ऐसे में केवल हज कमेटी के सचिव और अधिकारियों ने ही हाजियों का स्वागत किया. सालों से चली आ रही परंपरा इस बार टूटती हुई दिखाई दी.

इस बीच उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने हाजियों के परिजनों और रिश्तेदारों से अपील की है कि वर्तमान में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य चल रहा है. ऐसे में हज यात्रियों को रिसीव करने के लिए कम से कम संख्या में लोग एयरपोर्ट पहुंचें, ताकि भीड़भाड़ और यातायात संबंधी समस्याओं से बचा जा सके. कमेटी ने यह भी बताया है कि एयरपोर्ट पर पार्किंग स्थल सीमित होने के कारण वाहन लेकर आने वाले लोग उड़ान के आगमन समय से लगभग आधा घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंचें. निर्माण कार्य के चलते पार्किंग और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे जाम की स्थिति बनने की आशंका है.

हज कमेटी ने परिजनों को सलाह दी है कि यदि उन्हें अपने वाहन को अधिक समय तक पार्क करना हो तो वे हज हाउस, सरोजनीनगर में वाहन खड़ा कर सकते हैं. हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि वापसी के समय हज हाउस में हाजियों और उनके परिजनों के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है.

हिंदूफोबिया पर अमेरिका में बड़ा एक्शन, संसद में आया प्रस्ताव, 32 सांसदों ने किया समर्थन

(जीएनएस)।

अमेरिका में हिंदू-अमेरिकी समुदाय के योगदान को लेकर एक अहम राजनीतिक पहल को नया समर्थन मिला है। भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को अब कांग्रेसमैन रो खन्ना का भी समर्थन मिल गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका की इकोनॉमी, एजुकेशन, साइंस, हेल्थकेयर और सोशल डेवलपमेंट में हिंदू समुदाय की भूमिका को सम्मान देना है।

साथ ही इसमें हिंदूफोबिया, धार्मिक नफरत और हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों की कड़ी निंदा की गई है। यह कदम हिंदू-अमेरिकी समुदाय की पहचान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या है यह नया प्रस्ताव?

यह प्रस्ताव अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार द्वारा पेश किया गया था। इसका मकसद हिंदू-अमेरिकी समुदाय के योगदान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देना है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू समुदाय ने अमेरिका के अलग-अलग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा धार्मिक भेदभाव और नफरत के खिलाफ मजबूत संदेश देने की भी कोशिश की गई है। यह प्रस्ताव

जनवरी 2025 में पेश हुआ था और तब से लगातार इसे नए सांसदों का समर्थन मिल रहा है।

रो खन्ना के समर्थन का क्या महत्व है?

कैलिफोर्निया से सांसद फङ्ग डँल्लल्लं का समर्थन मिलने के बाद इस प्रस्ताव को और मजबूती मिली है। रो खन्ना भारतीय मूल के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू-अमेरिकी समुदाय ने देश की तरक्की में अहम योगदान दिया है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की नफरत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। उनके समर्थन से प्रस्ताव को दोनों पार्टियों के सांसदों के बीच अधिक चर्चा और समर्थन मिलने की संभावना बढ़ गई है।

हिंदू-अमेरिकी समुदाय का अमेरिका में योगदान

प्रस्ताव में बताया गया है कि हिंदू-अमेरिकी समुदाय ने टेक्नोलॉजी, मेडिकल, एजुकेशन, बिजनेस और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाई है। हजारों हिंदू-अमेरिकी प्रोफेशनल्स अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों, यूनिवर्सिटीज और हेल्थ सेक्टर में भारतीय मूल के लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं। यही वजह है कि सांसदों का मानना है कि इस समुदाय के योगदान को औपचारिक पहचान मिलनी चाहिए और उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जाना चाहिए।

हिंदूफोबिया और मंदिरों पर हमलों को लेकर चिंता

प्रस्ताव में हिंदूफोबिया और हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती नफरत पर भी चिंता जताई गई है। हाल के वर्षों में कुछ हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ तथा धमकी जैसी घटनाएं सामने आई हैं। सांसदों का कहना है कि किसी भी धर्म के लोगों को डर के माहौल में नहीं रहना चाहिए। इसलिए यह प्रस्ताव सिर्फ सम्मान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी संदेश देता है। यह कदम धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

कैंसर कितना गंभीर है? पहले ही चल जाएगा पता, PGI लखनऊ के वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी

(जीएनएस)।

लखनऊ। ब्लड कैंसर मल्टीपल मायलोमा को लेकर संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइएमएस) के शोधार्थियों ने एक ऐसे संकेतक (मार्कर) की पहचान की है, जिससे बीमारी की गंभीरता का अंदाजा पहले से लगाया जा सकेगा।

जिन मरीजों का सीरम फ्री लाइट चेन (एसएफएलसी) रेशियो सामान्य या लगभग सामान्य रहता है, उनमें बीमारी अपेक्षाकृत कम आक्रामक होती है। इलाज का असर भी बेहतर देखने को मिलता है।

अध्ययन में कुल 306 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें 240 मरीज मल्टीपल मायलोमा से पीड़ित थे। इनमें 9.6 प्रतिशत मरीजों का एसएफएलसी रेशियो सामान्य पाया गया। ऐसे मरीजों में बीमारी का असर कम गंभीर रहा और इलाज के प्रति प्रतिक्रिया भी बेहतर मिली।

सबसे अहम बात यह रही कि नार्मल एसएफएलसी रेशियो वाले

88.9 प्रतिशत मरीजों में इलाज के बाद वेरी गुड पार्टियल रिस्पांस देखा गया, जबकि असामान्य एसएफएलसी रेशियो वाले मरीजों में यह आंकड़ा 65.4 प्रतिशत रहा।

शोधार्थियों के मुताबिक नार्मल या लगभग नार्मल एसएफएलसी रेशियो वाले मरीजों में बीमारी कम खतरनाक हो सकती है। उनका शरीर इलाज पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। भविष्य में यह जांच मल्टीपल मायलोमा मरीजों की जोखिम श्रेणी तय करने में अहम बायोमार्कर साबित हो सकती है।

दुनिया में हर साल आ रहे नए मामले

मल्टीपल मायलोमा अपेक्षाकृत कम पाया जाने वाला गंभीर ब्लड कैंसर है। दुनियाभर में हर साल बड़ी संख्या में इसके नए मामले सामने आते हैं। भारत में भी यह ब्लड कैंसर के प्रमुख प्रकारों में शामिल है। यह बीमारी आमतौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ज्यादा देखी जाती है, हालांकि अब कम उम्र के मरीजों में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं।

मल्टीपल मायलोमा ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। इसमें शरीर की प्लाज्मा कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। सामान्य स्थिति में ये कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबाडी बनाती हैं, लेकिन बीमारी होने पर ये असामान्य प्रोटीन बनाने लगती हैं। इससे हड्डियों में दर्द, कमजोरी, खून की कमी और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

इन्होंने किया शोध

एसजीपीजीआइएमएस के हेमेटोलाजी विभाग के डॉ. मनीष के. सिंह, डा. संजीव यादव, डॉ. अक्षिता पांडेय, डा. खलीकुर रहमान, डॉ. मोना विजयरण, डॉ. पूरवी कपूर, डॉ. सायन सिन्हा राय, डॉ. रुचि गुप्ता, डॉ. दिनेश चंद्र, डॉ. कौशल कुमार और डॉ. विनीता शर्मा इस शोध से जुड़े रहे।

विभागाध्यक्ष प्रो. राजेश कश्यप के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय जर्नल इंटरनेशनल जर्नल आफ लेबोरेटरी हेमेटोलाजी ने स्वीकार किया है।